खास-खबरें

कलेक्टर की अध्यक्षता में समय सीमा की बैठक संपन्न

उमरिया। सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का शत प्रतिशत निराकरण करनें के कलेक्टर ने दिए निर्देश फोटो उमरिया 19 मई । कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में समय सीमा की साप्ताहिक बैठक संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर व्दारा सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए कहा कि सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों का शत प्रतिशत निराकरण किया जाए । समय सीमा की साप्ताहिक बैठक में कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन ने मुख्यमंत्री निवास से प्राप्त आवेदनों, आयुक्त शहडोल संभाग कार्यालय से प्राप्त आवेदनो तथा जनसुनवाई, न्यायालयीन प्रकरणों, मानवाधिकार के पत्रों, फैक्ट न्यूज आदि की समीक्षा करते हुए जिला प्रमुख अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी दायित्वों का निर्वहन समय सीमा में अनिवार्य रूप से करें।

नगर परिषद डिंडौरी को नगर पालिका परिषद बनाए जाने को लेकर बैठक आयोजित

डिण्डोरी। नगर परिषद डिंडौरी को नगर पालिका परिषद में अपग्रेड किए जाने संबंधी शासन के प्रस्ताव पर आज जनपद पंचायत डिंडौरी में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में इस प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई तथा क्षेत्रीय विकास एवं प्रशासनिक आवश्यकताओं पर विचार किया गया। इस बैठक में बताया गया कि डिंडौरी के चारों ओर लगभग 10 कि.मी. के दायरे में आने ग्रामों के सचिवों को आमंत्रित किया गया था।

कमिश्नर वीडियो कान्फ्रेंसिंग से आज करेंगे समीक्षा

रीवा । कमिश्नर रीवा संभाग बीएस जामोद 21 मई को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्धारित एजेण्डा बिन्दुओं की समीक्षा करेंगे। बैठक कमिश्नर कार्यालय के एनआईसी केन्द्र से शाम 4 बजे आरंभ होगी। बैठक में गेंहू उपार्जन, खाद्य सुरक्षा योजना तथा संबल पोर्टल की ई केवाईसी अपडेशन, राजस्व प्रकरणों के निराकरण, ई ऑफिस व्यवस्था, जल गंगा संवर्धन अभियान तथा संवाद से समाधान अभियान की समीक्षा की जाएगी। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के क्षेत्र भ्रमण की भी समीक्षा की जाएगी। संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा अन्य अधिकारी बैठक में शामिल होंगे।

विभागीय समन्वय से तैयार कराएं बिजनेस प्लान : सीईओ जिला पंचायत

मंडला। कलेक्ट्रेट के गोलमेज कक्ष में सीईओ जिला पंचायत श्री श्रेयांश कूमट की अध्यक्षता में कृषि और कृषि से जुड़े हुए अन्य विभागों की एपीसी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सहकारिता, पशुपालन, उद्यानिकी, मत्स्य पालन, आत्मा परियोजना तथा कृषि विभाग के जिला अधिकारियों ने विभागवार प्रस्तुतिकरण किए। सीईओ जिला पंचायत ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी एलाईड डिपार्टमेंट विभागीय समन्वय से बिजनेस प्लान तैयार कराएं, जिससे जिले के कृषकों को बेहतर अवसर मिल सके। बैठक में पैक्स कम्प्यूटराईजेशन, खरीफ सीजन का फसल ऋण वितरण, ऋण वसूली, खाद्य प्रसंस्करण, मार्केटिंग, पीएम एफएमई योजना, मुनगा पौधारोपण की तैयारी, यूरिया, एसएसपी, एनपीके, डीएपी की उपलब्धता एवं भंडारण, मृदा परीक्षण, कस्टम हायरिंग, नरवाई प्रबंधन, हेप्पीसीडर, सुपरसीडर की उपलब्धता, डेयरी केसीसी, बकरी पालन, कामधेनू योजना, कुक्कुट पालन, फिश पार्लर आदि विषयों पर समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिये गये।

जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर में 22 मई को लगाया जाएगा , नसबंदी शिविर

नरसिंहपुर। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत आवश्यकता पूर्ति के लिए जिले में माह मई 2025 में जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर में महिला एवं पुरूष नसबंदी- एनएसव्हीटी/ एलटीटी फिक्स डे स्टेटिक सेवा स्थल चिन्हांकित किया गया है। फिक्स डे स्टेटिक सेवा स्थल पर नियमानुसार मानकों के आधार पर सेवा दी जायेगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नरसिंहपुर ने बताया कि नरसिंहपुर जिला एवं जिले के बाहर के नसबंदी के हितग्राहियों के लिए 22 मई 2025 को जिला चिकित्सालय में महिला एवं पुरूष नसबंदी- एनएसव्हीटी/ एलटीटी फिक्स डे स्टेटिक सेवा स्थल चिन्हांकित किया गया है। शिविर स्थल पर मरीज का पंजीयन, शिविर के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी, जांच, पैथौलॉजी, ऑपरेशन, शिफटिंग एवं डिस्चार्ज समस्त व्यवस्थायें एवं आवश्यक दवाईयां की व्यवस्था शहरी एवं स्वास्थ्य केन्द्र नरसिंहपुर द्वारा की जावेगी।

एक जून से जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित होगा विशेष आधार कैंप

सभी विभागीय अधिकारी ई-ऑफिस प्रणाली का व्यवस्थित एवं सुचारू रूप से करें संचालन :कलेक्टर

अनुपपुर

कलेक्टर हर्षल पंचोली ने कहा है कि जिले में आधार कार्ड में त्रुटियों एवं अपूर्ण जानकारी के कारण जिले के अनेक नागरिक शासन की विभिन्न कल्याणकारी एवं जनहितैषी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए 01 जून से जिले के सभी नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष आधार पंजीयन एवं सुधार कैंप आयोजित किए जाएंगे।

कलेक्टर ने जिला गवर्नेंस मैनेजर को निर्देशित किया कि 25 मई तक सभी नगरीय क्षेत्रों के वार्डों एवं ग्राम पंचायतों के अनुसार कैंप का विस्तृत कैलेंडर तैयार कर लिया जाए, जिससे प्रत्येक क्षेत्र में नियत तिथि पर कैंप आयोजित किए जा सकें। उन्होंने कहा कि इन कैंपों का संचालन पूर्णत: सुचारू, पारदर्शी एवं नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखकर किया जाए तथा अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुँचाने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली आज कलेक्ट्रेट कार्यालय के नर्मदा सभागार में आयोजित समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। बैठक में वन मंडलाधिकारी अनूपपुर श्री विपिन पटेल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री तन्मय वशिष्ठ शर्मा, अपर कलेक्टर श्री दिलीप कुमार पाण्डेय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनूपपुर श्री कमलेश पुरी, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पुष्पराजगढ़ श्री सुधाकर सिंह बघेल, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जैतहरी श्रीमती अंजली द्विवेदी सहित जिले के सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली ने ई-ऑफिस प्रणाली की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्यालयीन कार्यों को आधुनिक, पारदर्शी और दक्ष बनाने हेतु ई-ऑफिस प्रणाली का पूरी जिम्मेदारी के साथ संचालन किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी शीघ्र अपना डिजिटल हस्ताक्षर बनवाएं तथा समस्त पत्राचार एवं फाइलों में हस्ताक्षर डिजिटल माध्यम से ही करें, जिससे कार्यों में गति और पारदर्शिता बनी रहे। कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिए कि यदि आवश्यक हो तो विभागीय लिपिकों को ई-ऑफिस प्रणाली की पुन: प्रशिक्षण देकर दक्ष किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी को ई-ऑफिस की प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी जाए, ताकि यह प्रणाली जिले में सफलतापूर्वक और सुचारू रूप से लागू की जा सके।

साथ ही कलेक्टर ने अपर कलेक्टर को निर्देशित किया कि वे विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण कर ई-ऑफिस क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति का जायजा लें। कलेक्टर ने जिले के समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारियों एवं जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से समग्र आईडी के माध्यम से आधार ई-केवाईसी की प्रगति की समीक्षा की।

समय-सीमा बैठक संपन्न

सिवनी

कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन की अध्यक्षता में सोमवार 19 मई को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा बैठक आयोजित हुई। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री नवजीवन विजय, अपर कलेक्टर श्री सी एल चनाप, अपर कलेक्टर सुश्री सुनीता खण्डायत, एसडीएम सुश्री मेघा शर्मा सहित सभी विभागों के कार्यालय प्रमुख उपस्थित थे।

इसी तरह विभिन्न विभागों के खंडस्तरीय अधिकारी वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में जुड़े थे। बैठक में कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन ने सीएम हेल्पलाईन, समय-सीमा में दर्ज प्रकरण, जनसुनवाई आवेदनों के निराकरण स्थिति, विभिन्न आयोग से प्राप्त पत्रों में लंबित कार्यवाही के साथ ही शासन की विभिन्न योजनाओं में प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिये। कलेक्टर सुश्री जैन ने सीएम हेल्प लाईन में विगत बैठक से कम प्रगति वाले विभाग प्रमुखों को चेतावनी दी। उन्होंन पीडब्लूडी, लोक स्वास्थ्य एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों को अधिकतम शिकायतों को संतुष्टि से बंद कराने के निर्देश दिये। इसके अतिरिक्त सीएम हेल्प लाईन शिकायतों में अपडेट प्रतिवेदन डालने के निर्देश सभी विभाग प्रमुखों को दिये हैं।

कलेक्टर सुश्री जैन ने सभी राजस्व अधिकारियों को फॉर्मर रजिस्ट्री के लिए लंबित प्रकरणों के अनुभागवार समीक्षा करते हुए 60 प्रतिशत से कम प्रगति वाले पटवारियों की विभागीय जांच प्रस्तावित करने के निर्देश दिये हैं।

इसी तरह राजस्व रिकॉर्ड के डिजिटाईजेशन की कार्यवाही शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश सभी अनुविभागीय अधिकारियों को दिये हैं। कलेक्टर सुश्री जैन ने सीमांकन प्रकरणों की समीक्षा में धनौरा में लक्ष्य से कम सीमांकन पाये जाने को लेकर तहसीलदार को नोटिस जारी करने के निर्देश दिये हैं। कलेक्टर सुश्री जैन ने नगरपालिका सीएमओ सिवनी को समग्र ई-केवायसी की कम प्रगति को लेकर नोटिस जारी किया है साथ ही वार्डवार अभियान चलाकर लंबित ई-केवायसी पूर्ण कराने के निर्देश सभी सीएमओ और सीईओ जनपदों को दिये गये हैं।

पात्र हितग्राहियों के ईकेवायसी से शेष अपात्र सदस्यों के पोर्टल से विलोपन की कार्यवाही करें : कलेक्टर

रीवा

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित उचित मूल्य दुकानों से खाद्य सुरक्षा योजना के हितग्राहियों को हर माह निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न दिया जा रहा है। शासन द्वारा एक जून से स्मार्ट खाद्यान्न वितरण व्यवस्था लागू की जा रही है।

इस व्यवस्था का लाभ लेने के लिए प्रत्येक राशन कार्ड में दर्ज हितग्राही का ई केवाईसी होना अनिवार्य है। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने सभी राशन कार्डधारियों से अपील करते हुए कहा है कि इस माह का खाद्यान्न लेने के लिए उचित मूल्य दुकान जाने पर सभी सदस्यों का ई केवाईसी करा लें। ई केवाईसी न कराने पर यह माना जाएगा कि राशन कार्ड में दर्ज सदस्य वर्तमान में दर्ज पते पर नहीं रह रहा है। इसे स्थाई पलायन मानते हुए उसका नाम राशन कार्ड से पृथक किया जाएगा। ई केवाईसी न कराने पर 31 मई के बाद खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उचित मूल्य दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए ई केवाईसी तत्काल करा लें। इसके लिए उचित मूल्य दुकान के सेल्समैन से संपर्क करके पीओएस मशीन के माध्यम से पूरी जानकारी एम राशन मित्र पोर्टल पर दर्ज करें। कलेक्टर ने एसडीएम जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, जिला आपूर्ति अधिकारी तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को ई केवाईसी से शेष अपात्र सदस्यों का पोर्टल से नाम 31 मई तक विलोपित करने के निर्देश दिये हैं।

कलेक्टर ने कहा है कि जो व्यक्ति उचित मूल्य दुकान में आकर पूरी जानकारी प्रस्तुत कर दे उसका ई केवाईसी तत्काल कर दें। खाद्यान्न वितरण के बाद उचित मूल्य दुकान के सेल्समैन अन्य कर्मचारियों के साथ शिविर लगाकर शेष बचे हितग्राहियों की ई केवाईसी कराएं। उचित मूल्य दुकानवार सूची उपलब्ध करा दी गई है।

सीएम हेल्प लाईन में लंबित शिकायतों का अधिकारी गंभीरता पूर्वक करें निराकरण : कलेक्टर

सिंगरौली

सीएम हेल्प लाईन में लंबित शिकायतों का गंभीरता पूर्वक समय सीमा के अंदर निराकरण किया जाना विभागीय अधिकारी सुनिश्चित करे। तथा राजस्व अधिकारी अपने अपने अनुभागो के अंतर्गत लंबित राजस्व प्रकरणो का अभियान चलाकर शत प्रतिशत निरकारण कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करे उक्त आशय का निर्देश कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समय सीमा बैठक के दौरान कलेक्टर श्री चन्द्र शेखर शुक्ला के द्वारा जिलाधिकारियों को दिया गया।

कलेक्टर श्री शुक्ला ने सीएम हेल्प लाईन में लंबित शिकायतों एवं समाधान विंदु पर लंबित आवेदनों के निराकरण के प्रगति की जानकारी विभागवार लेने के पश्चात निर्देश देते हुयें कहा कि कुछ विभागीय अधिकारियों के द्वारा सीएम हेल्प लाईन में लंबित शिकायतों के निराकरण में गंभीरता पूर्वक रूचि नही ली जा रही है जिसके कारण जिले की रैंकिंग प्रभावित हो रही है।

जो अत्यन्त ही खेदजनक है कलेक्टर ने कड़े निर्देश देते हुयें कहा कि लंबित शिकायतो का दो दिवस के अंदर संतुष्टि पूर्वक निराकरण कर अवगत कराए। साथ ही समाधान विंदु में लंबित आवेदन का भी समय पर निराकरण सुनिश्चित करे। कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिए कि यदि संबंधित विभागीय अधिकारियों के द्वारा लंबित शिकायतों का समय पर निराकरण नही किया गया गया जिले की रैंकिंग प्रभावित होगी तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेंगी। कलेक्टर ने सीमांकन के लंबित प्रकरणो की समीक्षा करते हुयें निर्देश दिए कि राजस्व अधिकारी अभियान चलाकर सीमांकन के लंबित प्रकरणो का निराकरण का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। कलेक्टर ने ई केवायसी की समीक्षा करते हुयें संबंधित विभागीय अधिकारी को निर्देश दिए कि लक्ष्य के अनुरूप शत प्रतिशत ईकेवायसी पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायें। बैठक के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गजेन्द्र सिंह नागेश, संयुक्त कलेक्टर संजीव पाण्डेय, एसडीएम सृजन बर्मा, राजेश शुक्ला, आयुक्त नगर निगम डी.के शर्मा, डिप्टी कलेक्टर माइकेल तिर्की, जिला पंचायत के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनुराग मोदी सहित जिलाधिकारी उपस्थित रहे।

समाधान ऑनलाइन के आवेदनों पर तत्काल कार्यवाही करें : डॉ सोनवड़े

रीवा

कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में आयुक्त नगर निगम डॉ सौरभ सोनवड़े ने टीएल पत्रों के निराकरण की समीक्षा की। बैठक में डॉ सोनवड़े ने कहा कि समाधान ऑनलाइन के एजेण्डा बिन्दुओं में लंबित सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों पर तत्काल कार्यवाही करें।

गत तीन माह में फोर्स क्लोज किए गए प्रकरणों एवं मांग के आधार पर बंद किए गए प्रकरणों की भी पुनः समीक्षा कर लें। समाधान ऑनलाइन के एजेण्डा बिन्दुओं में लंबित प्रकरणों में स्वास्थ्य विभाग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग, राजस्व विभाग, श्रम विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग की प्रगति संतोषजनक नहीं है। अधिकारी आवेदनों का स्वयं अध्ययन कर उनमें तथ्यपूर्ण जवाब दर्ज कराएं। जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रम विभाग की योजनाओं तथा योजना विभाग के बिन्दुओं पर लंबित आवेदनों पर दो दिवस में कार्यवाही सुनिश्चित करें। लोक निर्माण विभाग, वन विभाग तथा पिछड़ावर्ग एवं अल्पसंख्य कल्याण विभाग एवं जल संसाधन विभाग डी श्रेणी में हैं। आवेदनों का सन्तुष्टिपूर्वक निराकरण करके विभाग की ग्रेडिंग में सुधार करें।

डॉ सोनवड़े ने कहा कि विद्युत मण्डल में भी बड़ी संख्या में आवेदन लंबित हैं तथा विभाग की रैंकिंग में ऊर्जा विभाग 52वें स्थान पर है। बिजली बिलों में सुधार के आवेदन आज ही निराकृत कराकर रैंकिंग में सुधार करें। कई बार निर्देश देने के बावजूद अभी भी सीएम हेल्पलाइन में शिकायतें एल-1 अधिकारी द्वारा बिना किसी कार्यवाही के एल-2 अधिकारी के पास भेजी जा रही हैं। आवेदनों में समय सीमा में कार्यवाही न करने वाले एल-1 अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करें। सभी एसडीएम नगरीय निकायों में प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े भू अधिकार पत्र तथा जमीन आवंटन संबंधी आवेदन दो दिवस में निराकृत करा दें।

नशामुक्त भारत अभियान की जिला स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न

मंडला। नशामुक्त भारत अभियान की जिला स्तरीय समिति की बैठक जिला योजना भवन में कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उपसंचालक सामाजिक न्याय द्वारा समिति को प्रगति से अवगत कराया गया। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने कहा कि स्कूल, कॉलेज के आसपास गुटखा, सिगरेट आदि विक्रय करने वालों पर प्रतिबंध लगाएं। समिति द्वारा आयोजित की जाने वाली कार्यशालाओं में एसडीएम, एसडीओपी, तहसीलदार तथा टीआई आवश्यक रूप से भाग लें। उन्होंने कहा कि राजस्व तथा पुलिस के अधिकारी आबकारी विभाग के साथ समन्वय करते हुए अवैध शराब तथा मादक पदार्थों की बिक्री की शिकायत मिलने पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें।

कलेक्टर ने ली समय-सीमा प्रकरणों की बैठक

भू-अर्जन के प्रकरणों में भूमि और परिसम्पत्तियों का अवार्ड एक साथ बनाएं

सतना

सोमवार को संपन्न समय-सीमा प्रकरणों की बैठक में कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने विभिन्न विभागों के समन्वय के मुद्दों पर चर्चा करते हुए कहा कि भू-अर्जन के प्रकरणों में भूमि और उस पर निर्मित परिसम्पत्तियों का अवार्ड एक साथ पारित किया जाना चाहिए।

समय-सीमा प्रकरणों की बैठक में वृक्षारोपण की तैयारी, जल गंगा संवर्धन अभियान, सीएम डैश बोर्ड के प्रकरण, स्थानांतरण के प्रस्ताव आदि के संबंध में समीक्षा की गई। इस मौके पर अपर कलेक्टर स्वप्निल वानखडे, आयुक्त नगर निगम शेर सिंह मीना, सीईओ जिला पंचायत संजना जैन, एसडीएम जीतेन्द्र वर्मा, एपी द्विवेदी, एलआर जांगडे, आरएन खरे, सुधीर बेक, अधीक्षण यंत्री विद्युत पीके मिश्रा सहित विभाग प्रमुख अधिकारी, जनपद के सीईओ तथा नगरीय निकायों के सीएमओ उपस्थित रहे।

समय-सीमा प्रकरणों की बैठक में सर्वप्रथम कलेक्टर ने रेल्वे, बरगी नहर बाणसागर एवं अन्य विभागों के भूमि आवंटन, भू-अर्जन के प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि समन्वय से संबंधित सभी विभाग अपने मुद्दे अगली टीएल से पहले पोर्टल में फीड करें। कलेक्टर ने कहा कि एक-दूसरे विभाग से जुडे समन्वय के मुद्दे टीएल बैठक में रखे और उनका समाधान करायें। भू-अर्जन के प्रकरणों में कलेक्टर ने कहा कि अर्जित की जानी वाली भूमि और उस पर निर्मित परि-सम्पत्तियों का मुआवजा अवार्ड अलग-अलग जारी करने की बजाय एक साथ सम्मिलित रूप से बनाये। जिले में भूमि और उस पर निर्मित सम्पत्ति का अलग-अलग अवार्ड पारित करने की परम्परा रही है।

कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को शासन द्वारा संधारित मंदिरों की निर्धारित प्रारूप में जानकारी शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। इसी प्रकार सभी महाविद्यालयों द्वारा जनभागीदारी समिति से किये गये और किये जाने वाले कार्यों की जानकारी अभी तक नहीं प्रस्तुत करने पर कलेक्टर ने नोडल प्राचार्य शास. स्वशासी महाविद्यालय सतना को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये।

स्पेशल खबर जल गंगा संवर्धन अभियान समय सीमा की बैठक संपन्न, जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा

कार्यों में तेजी लाने के निर्देश, ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत किए जाएं विशेष प्रयास : कलेक्टर

बुरहानपुर

सोमवार को संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर हर्ष सिंह की अध्यक्षता में समय सीमा की बैठक संपन्न हुई। कलेक्टर श्री सिंह ने विभागवार पत्रकों की समीक्षा करते हुए, समय-सीमा के भीतर निराकरण के निर्देश दिए।

बैठक में सीएम डेशबोर्ड अंतर्गत प्रगति की भी समीक्षा की गई एवं अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने हेतु निर्देशित किया गया। कलेक्टर श्री सिंह ने विभागवार गहनता के साथ सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने बारी-बारी से विभाग प्रमुख से

प्रकरणों की वस्तुस्थिती को लेकर चर्चा की। प्रगति नहीं मिलने पर कलेक्टर श्री सिंह ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सभी अधिकारी सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों पर प्राथमिकता और गंभीरता के साथ कार्य करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कोई भी शिकायत अधिक समय तक लंबित नहीं रहे, लापरवाही बरतने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। खाद्य विभाग को राशन वितरण एवं ई-केवायसी कार्य में तेजी लाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। जिले में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत विशेष प्रयास अंतर्गत आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, ईकेवायसी गैस कनेक्शन एवं सिकल सेल एनिमिया जांच इत्यादि महत्वपूर्ण कार्यों की समीक्षा की गई और निर्देशित किया कि अभियान के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले इस बात का ध्यान रखा जायें। जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा समय-सीमा बैठक के पश्चात् जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा भी हुई, इस दौरान कलेक्टर श्री सिंह ने जनपदों को पौधारोपण कार्ययोजना के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। बैठक में विधायक श्रीमति अर्चना चिटनिस ने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत किए जा रहे कार्य बारिश के पहले पूर्ण हो जाए।

वहीं शासकीय एवं प्रायवेट ट्यूबवेलों की जानकारी एकत्रित करने एवं चौपालों का आयोजन कर ग्रामीणों को जल संरक्षण का संदेश देने की भी बात कहीं गई। यह भी कहा गया कि जिले में आयोजित होने वाले शासकीय कार्यक्रमों में भी प्लास्टिक की जगह बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स का उपयोग किया जाये। बैठक में जिला पंचायत सीईओ सुश्री लता शरणागत, अपर कलेक्टर श्री वीरसिंह चौहान सहित अन्य जिला अधिकारीगण मौजूद रहे।